ख) किसी नवीनीकृत प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति की अवधि के लिए अथवा किसी नवीनीकृत प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति से छूट की अवधि के लिए वैध बने रहेंगे, जिसे उस सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम 2023 (2023 का 44) अथवा भारतीय तार अधिनियम, 1885, (1885 का 13) अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार नवीनीकृत किया गया हो, या जैसा भी मामला हो, छूट दी गई हो।

अध्याय 2

सार्वजनिक संपत्ति में भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण

6. सुविधा प्रदाता द्वारा आवेदन — (1) भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन अथवा अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए किसी सार्वजनिक संपत्ति में मार्ग का अधिकार चाहने वाले सुविधा प्रदाता को, संबंधित सार्वजनिक इकाई, जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण अथवा प्रबंधन है, द्वारा पोर्टल पर दिए गए प्रारूप और रीति और साथ ही उप-नियम (3) के अधीन निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों के साथ, ऐसे प्रारूप और रीति जैसा कि उस सार्वजनिक इकाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि किसी सुविधा प्रदाता को उप-नियम (1) के अधीन आवेदन करने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होती है, तो:

(क) सुविधा प्रदाता ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए संबंधित सार्वजनिक इकाई द्वारा पोर्टल पर दिए गए प्रारूप और रीति से आवेदन प्रस्तुत करेगा; और

(ख) सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर ऐसे सर्वेक्षण के लिए अनुमति प्रदान करेगी और ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदाता से कोई शुल्क नहीं लेगी जैसा कि अनुसूची के भाग-I में निर्दिष्ट किया गया है।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में सुविधा प्रदाता द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सूचना में सहायक दस्तावेज सम्मिलित होंगे-

(क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राधिकार, अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन अनुज्ञप्ति, अथवा ऐसे प्राधिकार अथवा अनुज्ञप्ति से छूट की एक प्रति, जैसा भी मामला हो;

(ख) बिछाए जाने वाले प्रस्तावित भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क का ब्यौरा;

(ग) यदि मार्ग का अधिकार विद्यमान दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित है तो ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के निर्मित रेखाचित्रों की प्रति;

(घ) कार्य के निष्पादन की विधि और अनुमानित अवधि का ब्यौरा;

(ङ) उस दिन के अनुमानित समय का ब्यौरा जब कार्य किए जाने की अपेक्षा है, यदि सुविधा प्रदाता को दिन के विशिष्ट समय के दौरान कार्य किए जाने की अपेक्षा है;

(च) उन अनुमानित व्ययों का ब्यौरा जो सुविधा प्रदाता द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य के परिणामस्वरूप ऐसी सार्वजनिक इकाई को उठाना पड़ेगा;

(छ) सर्वसाधारण को होने वाली असुविधा का ब्यौरा और ऐसी असुविधा को कम करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपाय;

(ज) कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का ब्यौरा;

(झ) ऐसे नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए स्थापित किए जाने वाले दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच से संबंधित सुविधा प्रदाता की आवश्यकता का ब्यौरा;

(ञ) किए गए आवेदन के संबंध में पत्राचार के प्रयोजनों के लिए सुविधा प्रदाता के कर्मचारियों के नाम और संपर्क का ब्यौरा; और

(ट) सुविधा प्रदाता की राय में, प्रस्तावित कार्य से संबंधित अथवा उससे संबंधित, सुसंगत किसी अन्य मामले का ब्यौरा।

(4) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ शुल्क का भुगतान किया जाएगा जैसा कि इन नियमों की अनुसूची के भाग-1 में निर्दिष्ट किया गया है:

परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी परियोजना से संबंधित किसी भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित मार्ग के अधिकार के लिए कोई शुल्क, प्रभार, किराया, वार्षिकी, अथवा किसी भी रूप में कोई अन्य वित्तीय लेवी अथवा अंशदान अथवा मुआवजा, नहीं लिया जाएगा।

7. सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति प्रदान करना — (1) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक इकाई:

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकती है, जैसा कि अपेक्षित हो:

परंतु सार्वजनिक इकाई ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हो, एक समेकित मांग पत्र में मांगेगी; और

(ख) आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सड़सठ दिनों की अवधि के भीतर अनुमति प्रदान करेगा, अथवा उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रीति से आगे बढ़ेगा।

(2) सार्वजनिक इकाई द्वारा दी गई अनुमति में:

(क) यह सुनिश्चित करना कि भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क का क्षेत्र अथवा क्रॉस-सेक्शन जिसके लिए मार्ग का अधिकार प्रदान किया गया है, डक्ट की लंबाई गुणन डक्ट के व्यास तथा डक्ट की संख्या गुणन के बराबर होगा; और

(ख) यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि क्या अनुमति उप-नियम (9) के साथ पठित उप-नियम (8) के खंड (क) के अधीन संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए वचनबद्धता और बैंक गारंटी, अथवा उप-नियम (8) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा के अधीन है; और

(ग) सार्वजनिक असुविधा को कम करने अथवा सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए समय और उपाय, मार्ग के अधिकार के निष्पादन की रीति और इस प्रकार स्थापित दूरसंचार नेटवर्क के प्रचालन और अनुरक्षण आवश्यकताओं संबंधी शर्तों सहित अन्य शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु सार्वजनिक इकाई नियम (6) के उप-नियम (3) के खंड (घ) के अधीन सुविधा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन की रीति पर उचित विचार करेगी।

any casing, coating, tube or pipe enclosing the same, and any appliances and apparatuses connected therewith for the purpose of fixing or insulating the same;

(o) "underground telecommunication network" means parts of a telecommunication network or telecommunication equipment established under the ground and includes ducts, manholes, marker stones, hand holes, submarine cables, telecommunication line, appliances and apparatuses for the purposes of establishment or maintenance of the telecommunication network.

(1)

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Application. – (1) These rules shall apply to permissions for right of way for telecommunication network.

(1)

(2) Any public entity shall exercise the powers under these rules upon an application made by any facility provider seeking right of way for telecommunication network.

(3) All applications, notifications, clarifications, permissions, objections or rejections under these rules, shall be made through the portal to the extent specified under these rules.

4. Public entity to appoint nodal officer. - Every public entity shall, within a period of thirty days from the date of notification of these rules, specify its nodal officer on the portal, for the purposes of these rules and any replacement of such officer shall also be specified on the portal by the concerned public entity within a period of seven days of such replacement.

5. Validity and renewal of permission for right of way. – The permission for right of way granted to a facility provider in respect of the underlying telecommunication network under these rules shall, unless such permission is terminated in accordance with these rules,—

(a) remain valid for a period coterminous with the term of authorisation or license, or exemption from such authorisation or license, granted or, as the case may be, exempted, by the Central Government; and

(b) continue to be valid for the term of any renewed authorisation or license, or the term of any renewed exemption from authorisation or license, renewed or, as the case may be, exempted, by that Government,

in accordance with the provisions of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), or the rules made thereunder.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT, OPERATION AND MAINTENANCE OF UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

6. Application by a facility provider. — (1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishment, operation or maintenance of underground telecommunication network, shall submit an application in such form and manner, as provided on the portal, by the concerned public entity which has ownership, control or management over such public property, along with supporting documents as specified under sub-rule (3), in such form and manner as may be specified by that public entity.

(1)

(2) Where a facility provider requires a survey to be undertaken to enable it to make the application under sub-rule (1)-

the facility provider shall submit an application in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity, for seeking permission to conduct such survey; and

the public entity shall, within seven days of receipt of such application, grant permission for such survey and shall not charge any fee, as specified in Part-1 of the Schedule, to the facility provider for grant of such permission.

(3) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the portal, in the application made under sub-rule (1) shall include-

(a) a copy of the authorisation under the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), or license under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), granted by the Central Government, or

exemption from such authorisation or license, as the case may be;

(b) details of the underground telecommunication network proposed to be laid;

(c) if the right of way pertains to existing telecommunication network, a copy of as-built drawings of such telecommunication network;

(d) details of the mode of and the estimated duration for execution of the work;

(e) details of the estimated time of the day when the work is expected to be done, in case the facility provider expects the work to be done during specific time of the day;

(f) details of the estimated expenses the public entity may incur in consequence of the work proposed to be undertaken by the facility provider;

(g) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;

(h) details of the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;

(i) details of the need of facility provider for access to the telecommunication network sought to be established, for operating and maintaining such network;

(j) names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made; and

(k) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with or related to the work proposed to be undertaken.

(4) Every application under sub-rule (1), shall be accompanied with fee as specified in Part-1 of the Schedule:

Provided that no fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy or contribution or compensation in any form, shall be applicable for right of way related to any underground telecommunication network pertaining to any project notified by the Central Government.

7. **Grant of permission by public entity . —** (1) Upon examination of an application received under sub-rule (1) of rule 6, the public entity may-

(a) seek clarifications or further documents, as may be required, through the portal, within a period of thirty days from the date of receipt of such application:

Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and

(b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (3) and sub-rule (4).

(1)

(2) The permission granted by the public entity shall-

(a) ensure that the area or cross-section of the underground telecommunication network for which right of way is granted shall be the length of duct multiplied by the diameter of the duct multiplied by the number of ducts;

(b) specify whether the permission is subject to the undertaking and bank guarantee for restoration of property under clause (a) of sub-rule (8) read with sub-rule (9), or compensation for any damage as specified in clause (b) of sub-rule (8); and

(c) specify other conditions including the time, and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, the mode of execution of the right of way and the conditions relating to the needs of operation and maintenance of the telecommunication network so established:

Provided that the public entity shall give due consideration to the mode of execution as specified by the facility provider under clause (d) of sub-rule (3) of rule 6.

(3) Where the public entity has reasons to reject the application for right of way, it shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider shall respond to such reasons on the portal, within a period of fifteen days therefrom.